पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 10601/2023

=====

1. विनायक कुमार, महादेव सिंह के सुपुत्र, वार्ड संख्या 5, डाकघर और थाना-लाखो, जिला-बेगुसराय, बिहार के निवासी।
2. कृष्ण कुमार, उदय मंडल के पुत्र, बिंदा सिंह गली, डाकघर और थाना-सुल्तानगंज, जिला-भागलपुर, बिहार के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अवर सचिव, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (बी. सी. ई. सी. ई.) अपने अध्यक्ष पटना, बिहार के माध्यम से।

.....प्रतिवादीगण

=====

- A. भारत का संविधान-अनुच्छेद 309-बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदात्मक रोजगार भुगतान नियम, 2019-चयन प्रक्रिया-न्यूनतम योग्यता-विज्ञापन में भिन्नता में-वैधानिक नियमों के विपरीत- शून्य एवं अवैध -कानून में न्यूनतम योग्यता-लागू है।(इसका उल्लेख किया गया है:- आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 3 एस. सी. सी. 55, कंडिका-27), (कंडिका-5,6)
- B. सेवा न्यायशास्त्र-स्थापित सिद्धांत-विज्ञापन और सेवा विनियमन के बीच विरोधाभास- बाद में लागू हुआ- (इसका उल्लेख है- कर्मचारी राज्य बीमा निगम बनाम भारत संघ और अन्य (2022) 11 एस. सी. सी. 392); (कंडिका-7 में)
- C. प्रवर्तन का प्रश्न-न्यायालय वैधानिक- विहित से परे की शर्त को नजरअंदाज करने के लिए बाध्य हैं-विश्वविद्यालय/संस्थान-यू0 जी0 सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त- ए. आई. सी. टी. ई. अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।(इसका उल्लेख किया गया है:- भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्य। बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा और अन्य परिषद (2001) 8 एस. सी. सी. 676), (पैरा-7); (CWJC क्र0 6379/2020; सूरज कुमार वर्मा बनाम। बिहार राज्य और अन्य) ; खंड पीठ सिविल रिट याचिका सं। 277/2021 भारत संघ और अन्य बनाम अतुल खरे)।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 10601/2023

=====

1. विनायक कुमार, महादेव सिंह के सुपुत्र, वार्ड संख्या 5, डाकघर और थाना-लाखो, जिला-बेगुसराय, बिहार के निवासी।
2. कृष्ण कुमार, उदय मंडल के पुत्र, बिंदा सिंह गली, डाकघर और थाना-सुल्तानगंज, जिला-भागलपुर, बिहार के निवासी।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. अवर सचिव, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. निदेशक, भूमि अभिलेख और सर्वेक्षण, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (बी. सी. ई. सी. ई.) अपने अध्यक्ष पटना, बिहार के माध्यम से।

.....प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति-

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री समीर कुमार, अधिवक्ता

श्री अजीत कुमार, अधिवक्ता,

श्री सौरभ सिंह अधिवक्ता,

राज्य के अधिवक्ता : श्री साजिद सलीम खान (एससी-25)

बि.सं.प्र.प्र.प. समिति के लिए : श्री प्रसून सिन्हा, अधिवक्ता

श्री अमरनाथ कुमार, अधिवक्ता

=====

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय:-

तारीख:23-01-2024

वर्तमान रिट याचिका नोडल अधिकारी, भूमि सुधार और राजस्व विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत विज्ञापन संख्या बि.सं.प्र.प्र. समिति/राजस्व/डी. एल. आर. एस.-2023/01 दिनांक 11.04.2023 वाले विज्ञापन को खारिज करने के लिये दायर की गयी हैं। जिसके द्वारा विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन और विशेष सर्वेक्षण किरानी के पदों पर भर्ती करने के उद्देश्य से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना ने दिनांक 10.11.2018 के संकल्प के माध्यम से अनुबंध के

आधार पर उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां करने के लिए एक योजना जारी की थी और इसके खंड-4 में न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, चूँकि याचिकाकर्ता सं.- 1 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद के लिए स्पर्धा करने वाला है जबकि याचिकाकर्ता सं.- 2 विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद के लिए, यह न्यायालय केवल इन दो पदों के दृष्टिकोण से अपने विचार को सीमित करेगा।

3. उपरोक्त संकल्प में दिनांक 10.11.2018 में, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर नियुक्त होने के लिए उम्मीदवार के पास न्यूनतम योग्यता दो साल के अनुभव के साथ सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है जबकि स्पेशल सर्वे अमीन के पद के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार ने तब बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदात्मक कर्मचारी वेतनमान नियम, 2019 को अधिसूचना दिनांक 27.02.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया था और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता क्रमशः सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है और न्यूनतम दो साल का अनुभव और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखा। उक्त नियमों को अधिसूचना दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से संशोधित किया गया था, हालांकि, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समान रही। इसके बाद, राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन 11.04.2023 को जारी किया गया था, हालांकि, उक्त विज्ञापन में न्यूनतम योग्यता बदल दी गई है और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद के लिए, निर्धारित न्यूनतम योग्यता संबंधित राज्य के राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (इसके बाद 'एस. बी. टी. ई.' के रूप में संदर्भित) के साथ पंजीकृत और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा है। इसी तरह, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता संबंधित राज्य के एस. बी. टी. ई. में पंजीकृत और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा है।

4. हालांकि, याचिकाकर्ता सं.- 1 के बारे में कहा गया है कि उसने दिनांक 11.04.2023 के उपरोक्त विज्ञापन के अनुसरण में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर नियुक्त होने के लिए आवेदन नहीं किया है, हालांकि, याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील का यह निवेदन है कि चूंकि जिस संस्थान से याचिकाकर्ताओं ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है, वह ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, हालांकि वह वि. अ. आ. द्वारा मान्यता प्राप्त है, याचिकाकर्ता संख्या 1, पात्र नहीं होने के कारण, आवेदन नहीं किया था, हालांकि याचिकाकर्ता नं. 2 ने विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद के लिए आवेदन किया था, हालांकि, परामर्श के समय उसकी उम्मीदवारी को नहीं माना गया है, और इसके बजाय याचिकाकर्ता संख्या 2 को लिखित रूप में इस तथ्य का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि जिस संस्थान से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त किया है, उसे एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि चयन प्रक्रिया के संचालन के उद्देश्यों के लिए एक विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता, कानून/नियमों में निर्धारित योग्यताओं के विपरीत नहीं हो सकती है। इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां करने के लिए बी. सी. ई. सी. ई. बी. द्वारा जारी किया गया प्रश्नगत उपरोक्त विज्ञापन दिनांक 11.04.2023, संबंधित राज्य के एस. बी. टी. ई. में पंजीकृत और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल के डिप्लोमा के रूप में उक्त दो पदों के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित करता है, हालांकि, उक्त निर्धारण में निर्धारित न्यूनतम पात्रता योग्यता के विपरीत है। बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदात्मक रोजगार भुगतान नियम, 2019 (जिसे बाद में 'नियम, 2019' के रूप में संदर्भित किया गया है में निर्धारित न्यूनतम पात्रता योग्यता के विपरीत हैं), जैसा कि दिनांक 20.12.2022 के अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, जो अवैध और सुव्यवस्थित कानून के विपरीत है, विशेष रूप से इस कारण से कि उपरोक्त

नियम, 2019, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए वैधानिक नियम हैं।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मामले के उपरोक्त पहलू के संबंध में, माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **आशीष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2018) 3 एस सी सी 55** में प्रतिवेदित, मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब विज्ञापन और वैधानिक नियमों में भिन्नता होती है, तो यह वैधानिक नियम होते हैं जो प्राथमिकता लेते हैं। इस संबंध में, **आशीष कुमार** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए उक्त निर्णय के पैराग्राफ 27 को यहाँ पुनः प्रस्तुत करना फायदेमंद होगा:-

"27. विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक निर्धारण का रास्ता देना होगा। इस प्रकार, वैधानिक नियमों में निर्धारित योग्यता को देखते हुए, अपीलकर्ता योग्यता को पूरा करता है और पद के लिए चुने जाने के बाद उसे नियुक्ति करने से इनकार करना मनमाना और अवैध है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब विज्ञापन और वैधानिक नियमों में भिन्नता होती है, तो यह वैधानिक नियम होते हैं जो प्राथमिकता लेते हैं। इस संदर्भ में, माली मजहर सुल्तान बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग, निर्णय के पैरा 21 में इस न्यायालय के फैसले में उपरोक्त प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव से है:(एस. सी. सी. पी. 512)

"21.वर्तमान विवाद उत्पन्न हो गया है क्योंकि पी. एस. सी. द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया है कि जो उम्मीदवार 1-7-2001 और 1-7-2002 के बीच आयु के भीतर थे, उन्हें परीक्षा के लिए आयु के भीतर माना जाएगा। निस्संदेह, बहिष्कृत उम्मीदवार विज्ञापन के अनुसार योग्य आयु के थे, लेकिन सेवा में भर्ती केवल नियमों के अनुसार की जा सकती है और विज्ञापन में त्रुटि, यदि कोई हो, नियमों को अवहेलना नहीं कर सकती है और उम्मीदवार के पक्ष में अधिकार पैदा नहीं कर

सकती है, यदि अन्यथा नियमों के अनुसार पात्र नहीं है। आयु में छूट केवल तभी दी जा सकती है जब नियमों के तहत अनुमति हो और विज्ञापन के आधार पर नहीं। यदि पी. एस. सी. द्वारा विज्ञापन जारी करने के समय नियमों की व्याख्या गलत थी, तो उसके आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, इस प्रश्न का उत्तर नियमों की व्याख्या पर निर्भर करेगा।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **राज्य बीमा निगम बनाम भारतीय संघ और अन्य, (2022) 11 एस. सी. सी. 392** में प्रतिवेदित कर्मचारियों के मामले में दिए गए निर्णय का भी यह तर्क देते हुए उल्लेख किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि यह सेवा न्यायशास्त्र का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी विज्ञापन और सेवा विनियमों में कथन के बीच टकराव की स्थिति में, बाद वाला प्रबल होगा। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया है। **भारतीदासन विश्वविद्यालय और एक अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और अन्य, (2001) 8 एस. सी. सी. 676** में प्रतिवेदित मामले में दिए गए निर्णय पर भी यह तर्क देते हुए भरोसा किया है कि यू. जी. सी. द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय/संस्थान को ए. आई. सी. टी. ई. अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

8. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, याचिकाकर्ता सं.- 1 ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल से डिप्लोमा प्राप्त किया है जबकि याचिकाकर्ता सं.- 2 ने गलगोटियास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा प्राप्त किया है। और दोनों विश्वविद्यालय वि. अ. आ. द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इस संबंध में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के एक समन्वय पीठ द्वारा **दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 6379/2020 (सूरज कुमार वर्मा बनाम बिहार राज्य और अन्य)** और अन्य समान मामले में दिनांक 23.06.2021 को दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर स्थित विद्वान **खंड पीठ द्वारा (खंडपीठ) दीवानी रिट**

याचिका संख्या 227/2021 (भारत संघ और अन्य बनाम अतुल खरे) मामले में दिनांक 30.01.2023 को दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक निर्धारण को रास्ता देना होगा।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील श्री साजिद सलीम खान ने वर्तमान मामले में दायर जवाबी हलफनामे का हवाला देते हुए प्रस्तुत किया है कि न तो विज्ञापन मुख्य रिट याचिका में संलग्न किया गया है और न ही उन संस्थानों/विश्वविद्यालयों का विवरण जहां से उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया है जिसका उल्लेख रिट याचिका में किया गया है और उनके आवेदन पत्रों की अस्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे को साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है। इसके विपरीत, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच पर, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता 1 सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय, भोपाल से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के आधार पर अनुबंध के आधार पर विशेष सर्वेक्षण अमीन के रूप में काम कर रहा है, एक तथ्य जिसे उन्होंने दबा दिया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसी रिट याचिकाएं जहां याचिकाकर्ता स्वच्छ हाथों से न्यायालय का दरवाजा नहीं खोलते हैं, उन्हें सीमा से बाहर फेंक दिया जाना आवश्यक है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पहले वर्ष 2019 में एक विज्ञापन जारी किया गया था और नियुक्तियां भी की गई थीं, जिसके बाद वर्ष 2022 में फिर से विज्ञापन जारी किया गया था, हालांकि, चयन की प्रक्रिया के दौरान, नियम, 2019 को अधिसूचना दिनांक 20.12.2022 के माध्यम से संशोधित किया गया था। इसलिए उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद, वर्तमान विज्ञापन यानी वर्ष 2023 का दिनांकित 11.04.2023 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन सहित उपरोक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु जारी किया गया है और उक्त दो पदों के लिए न्यूनतम पात्रता योग्यता संबंधित राज्य के एस. बी. टी. ई. में पंजीकृत और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल के डिप्लोमा के रूप में निर्धारित की गई है। यह भी प्रस्तुत किया

जाता है कि विज्ञापन दिनांक 11.04.2023 नियम, 2019 के संदर्भ में जारी किया गया है जैसा कि अधिसूचना दिनांक 20.12.2022 द्वारा संशोधित किया गया है। अंत में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 11.04.2023 के उपरोक्त विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड जैसा कि नियमों और विज्ञापन में निर्धारित किया गया है, संस्थानों को मान्यता देने की आवश्यकता के अनुरूप है, इस प्रकार दिनांकित 11.04.2023 के विज्ञापन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के विपरीत नहीं है, जैसा कि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और खारिज किए जाने के योग्य है।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत घोषित नियम, 2019, जैसा कि दिनांक 20.12.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और न्यूनतम दो साल का अनुभव है, जबकि विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के रूप में निर्धारित करता है, तथापि इसके विपरीत, दिनांक 11.04.2023 के विज्ञापन में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड सम्बंधित राज्य के ए. आई. सी. टी. ई. के साथ पंजीकृत और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा के साथ न्यूनतम दो साल का अनुभव जबकि विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद के लिए, संबंधित राज्य के एस. बी. टी. ई. द्वारा पंजीकृत और ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में विचार के लिए जो सीमित मुद्दा उत्पन्न होता है, जैसा कि अभिलेखों से निकाला जा सकता है, वह यह है कि क्या न्यूनतम विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर नियुक्तियां करने के लिए बी. सी. ई. सी. ई. बी. द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 11.4.2023 में निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं बिहार विशेष

सर्वेक्षण संविदा नियोजन वेतनमान नियमावली 2019 यथा अधिसूचना दिनांक 20.12.2022 द्वारा संशोधित में निर्धारित योग्यताओं के विपरीत हो सकता है तथ्य पर विचार करते हुए कि उपरोक्त नियम, 2019 वैधानिक नियम हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए हैं।

11. उपरोक्त मुद्दे का उत्तर, जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है, बहुत सरल है जैसा कि **आशीष कुमार** (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इससे पहले ही स्थगित कर दिया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विज्ञापन का कोई भी हिस्सा जो वैधानिक नियमों के विपरीत है, उसे वैधानिक निर्धारण के अनुसार रास्ता देना होगा। **आशीष कुमार** (उपरोक्त) के मामले में और **कर्मचारी राज्य बीमा निगम** (उपरोक्त) मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर विचार करते हुए यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करना उपयुक्त और उचित समझता है कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों के लिए दिनांक 11.04.2023 के विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं, कुछ हद तक जैसा कि दिनांक 20.12.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है, वे नियम, 2019 में निर्धारित योग्यताओं के विपरीत हैं, उन्हें शून्य माना जाएगा और वैधानिक निर्धारण में निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं प्रबल होंगी।

12. इस समय यह कहना पर्याप्त होगा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास वि. अ. आ. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य** (उपरोक्त) के मामले में तय किए गए कानून को देखते हुए ऐसे संस्थान/विश्वविद्यालय को ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा मान्यता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जिन विश्वविद्यालयों/संस्थानों को वि. अ. आ. द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन्हें ए. आई. सी. टी. ई. से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। 13. यहाँ यह इंगित करना प्रासंगिक हो सकता है कि इस न्यायालय के दिनांक 16.01.2024 के एक पूर्व आदेश द्वारा, जबकि इस न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका में शामिल मुद्दे को तैयार किया था और

उसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया था, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील को, उनके आग्रह पर, उत्तरदाताओं से निर्देश लेने के लिए समय दिया था कि क्या एक अपवाद के रूप में, याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को दिनांकित 11.04.2023 के उपरोक्त विज्ञापन के संदर्भ में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान वकील, निर्देशों पर प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब यह न्यायालय ऐसा निर्देश देता है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय वर्तमान मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ा है और वर्तमान निर्णय दे रहा है।

14. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और पूर्वगामी कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय, हालांकि प्रतिवादियों को क्रमशः विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों के लिए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश देना उपयुक्त और उचित समझता है, हालांकि, दिनांक 11.04.2023 के विज्ञापन को रद्द करने से खुद को रोकता है। इस कारण से कि सबसे पहले चयन प्रक्रिया एक उन्नत चरण में है और परामर्श भी पहले ही आयोजित किया जा चुका है, इसलिए उम्मीदवारों को अनुचित कठिनाई होगी और दूसरा, **भारतीदासन विश्वविद्यालय** एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, भारतीदासन विश्वविद्यालय एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में जब प्रवर्तन का प्रश्न उत्पन्न होता है, तो न्यायालय उन शर्तों को नजरअंदाज करने के लिए बाध्य होते हैं जो वैधानिक निर्धारण से परे दिखाई देते हैं, जहां तक विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों का संबंध है। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की चुनौती को सीमित सीमा तक, व्यक्तिगत रूप से, यानी कि न्यूनतम योग्यता की सीमा तक अनुमति दी है जो दिनांक 11.04.2023 के विज्ञापन में निर्धारित की गई है, जो नियम, 2019 के विपरीत है, जैसा कि दिनांक 20.12.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है।

इस प्रकार, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद से संबंधित विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यता नियम, 2019 में निर्दिष्ट योग्यताओं के विपरीत है, जैसा कि दिनांक 20.12.2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया है। यह न्यायालय यह देखेगा कि याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर दिनांक 11.04.2023 के उपरोक्त विज्ञापन के तहत नए सिरे से विचार किया जाएगा, लेकिन नियम, 2019 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 20.12.2022 द्वारा संशोधित किया गया है।

15. रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक अनुमति दी जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एस. बी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।